VIDYA BHAWAN BALIKA VIDYA PITH

शक्ति उत्थान आश्रम लखीसराय बिहार

class 12 commerce Sub. ECO/ B Date 3.6.2020

Teacher name – Ajay Kumar Sharma

INDIAN ECONOMY 1950–1990

Question 17:

Explain how import substitution can protect domestic industry.

ANSWER:

In the initial seven five year plans, India opted for import substitution strategy, which implies discouraging the imports of those goods that could be produced domestically. Import Substitution Strategy not only reduces an economy's dependence on the foreign goods but also provides impetus to the domestic firms. Government provides various financial encouragements, incentives, licenses to the domestic producers to produce domestically the import substituted goods. This would not only allow the domestic producers to sustain but also enables them to grow as they enjoy the protective environment. They need not to fear from any competition and also not to worry about their market share as license gives them the monopoly status in the domestic market. Being monopolist, they earn more profits and invest continuously in R&D and always look for new and innovative techniques. This gradually improves their competitiveness and when they are exposed to the international market they can survive and compete with their foreign counterparts.

आरंभिक सात पंचवर्षीय योजनाओं में, भारत ने आयात प्रतिस्थापन रणनीति का विकल्प चुना, जिसका तात्पर्य उन वस्तुओं के आयात को हतोत्साहित करना है, जिन्हें घरेलू स्तर पर उत्पादित किया जा सकता है। आयात प्रतिस्थापन रणनीति न केवल विदेशी वस्तुओं पर अर्थव्यवस्था की निर्भरता को कम करती है, बल्कि घरेलू फर्मों को प्रोत्साहन भी प्रदान करती है। सरकार घरेलू उत्पादकों को विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन, प्रोत्साहन, लाइसेंस प्रदान करती है ताकि घरेलू रूप से आयात किए गए माल का उत्पादन किया जा सके। यह न केवल घरेलू उत्पादकों को बनाए रखने की अनुमति देगा, बल्कि उन्हें सुरक्षात्मक वातावरण का आनंद लेने के लिए विकसित करने में सक्षम बनाता है। उन्हें किसी भी प्रतिस्पर्धा से डरने की जरूरत नहीं है और अपने बाजार हिस्सेदारी के बारे में भी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि लाइसेंस उन्हें घरेलू बाजार में एकाधिकार का दर्जा देता है। एकाधिकार होने के नाते, वे अधिक लाभ कमाते हैं और आर एंड डी में लगातार निवेश करते हैं और हमेशा नई और नई तकनीकों की तलाश

करते हैं। इससे धीरे-धीरे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होता है और जब वे अंतरराष्ट्रीय बाजार के संपर्क में आते हैं तो वे अपने विदेशी समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।

Question 18:

Why and how was private sector regulated under the IPR 1956?

ANSWER:

IPR 1956 was adopted in order to accomplish the aim of state controlling the commanding heights of economy. This policy was aligned with the Indian economy's inclination towards socialist pattern of system of Soviet Union. According to this resolution, industries were classified into following three categories:

Category 1: Those industries that are established and owned exclusively by the public sector.

Category 2: Those industries in which public sector will perform the primary role while the private sector will play the secondary role. That is, the private sector supplements the public sector in these industries.

Category 3: Those industries that are not included in Category 1 and Category 2 are left to the private sector.

These industries that were left to the private sector, the government owns an indirect control by the way of license. In order to initiate a new industry, private entrepreneurs should obtain license (or permit) from the government. By licensing system, tax holidays and subsidies government can promote industries in a backward region that will ,in turn, promote the welfare and development of that region. This was supposed to reduce regional disparities.

Further, in order to expand the scale of production, private sector needs to obtain license from government. This was supposed to keep a check on the production of goods that are socially undesirable and unwanted. Hence, the state fully controlled the private sector either directly or indirectly.

आईपीआर 1956 को अर्थव्यवस्था की कमांडिंग ऊंचाइयों को नियंत्रित करने वाले राज्य के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपनाया गया था। यह नीति सोवियत संघ की प्रणाली के समाजवादी पैटर्न के प्रति भारतीय अर्थव्यवस्था के झुकाव के साथ गठबंधन की गई थी। इस संकल्प के अनुसार, उद्योगों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था:

श्रेणी 1: वे उद्योग जो सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा विशेष रूप से स्थापित और स्वामित्व में हैं।

श्रेणी 2: वे उद्योग जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र प्राथमिक भूमिका निभाएंगे जबकि निजी क्षेत्र द्वितीयक भूमिका निभाएंगे। यानी निजी क्षेत्र इन उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र को पूरक बनाता है।

श्रेणी 3: वे उद्योग जो श्रेणी 1 और श्रेणी 2 में शामिल नहीं हैं, उन्हें निजी क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है।

ये उद्योग जो निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिए गए थे, सरकार लाइसेंस के माध्यम से एक अप्रत्यक्ष नियंत्रण का मालिक है। एक नया उद्योग शुरू करने के लिए, निजी उद्यमियों को सरकार से लाइसेंस (या परमिट) प्राप्त करना चाहिए। लाइसेंस प्रणाली द्वारा, कर अवकाश और सब्सिडी सरकार एक पिछड़े क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा दे सकती है जो बदले में, उस क्षेत्र के कल्याण और विकास को बढ़ावा देंगे। यह क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने वाला था।

इसके अलावा, उत्पादन के पैमाने का विस्तार करने के लिए, निजी क्षेत्र को सरकार से लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता है। यह उन सामानों के उत्पादन पर नजर रखने के लिए था जो सामाजिक रूप से अवांछनीय और अवांछित हैं। इसलिए, राज्य ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निजी क्षेत्र को पूरी तरह से नियंत्रित किया।